LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, February 03, 2026 / Magha 14, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, February 03, 2026 / Magha 14, 1947 (Saka)

CONTENTS PAGES

OBITUARY REFERENCE 1

ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION 1A – 30
(S.Q. NO. 41)

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS 31 – 50
(S.Q. NO. 42 – 60)

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS 51 – 280
(U.S.Q. NO. 461– 690)

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, February 03, 2026 / Magha 14, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, February 03, 2026 / Magha 14, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 91

ELECTIONS / NOMINATIONS TO COMMITTEES 291 - 95

(i) Committee on Estimates
(ii) Committee on Public Accounts
(iii) Committee on Public Undertakings
(iv) Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

MOTION RE: 14TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY 295

… 296

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 297 - 312

Dr. K. Sudhakar 297

Shri Manish Jaiswal 298

Shri Praveen Patel 298

Dr. Daggubati Purandeswari 299

Shri Shashank Mani 300

Shri Anurag Singh Thakur 300

Shri Rao Rajendra Singh	**301**
Shrimati Mahima Kumari Mewar	**301**
Shri Balabhadra Majhi	**302**
Shri P. P. Chaudhary	**302**
Dr. Anand Kumar Gond	**303**
Shri Chandra Prakash Joshi	**303**
Adv. Dean Kuriakose	**304**
Shri Satpal Brahamchari	**304**
Shri Ujjwal Raman Singh	**305**
Shri Gowaal Kagada Padavi	**305 - 06**
Shri Brijendra Singh Ola	**306**
Shri Ramashankar Vidharthi Rajbhar	**307**
Shri Neeraj Maurya	**307**
Shrimati Pratima Mondal	**308**
Shri T.M. Selvaganapathi	**308**
Shri Prabhakar Reddy Vemireddy	**309**
Shri Naresh Ganpat Mhaske	**309**
Shrimati Shambhavi	**310**
Shri Sudhakar Singh	**310**
Shri Amra Ram	**311**
Adv. Chandra Shekhar	**311**
Shri Chandra Prakash Choudhary	**312**

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS **313 - 16**
(Contd. -- Inconclusive)

Shri Rahul Gandhi **313 - 16**

… **317**

TEXT OF AMENDMENTS **318 - 37**

Shri G.M. Harish Balayogi -- (Speech Unfinished) **338**

RE: NAMING AND SUSPENSION OF MEMBERS **339**

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS **340**

… **341**

xxxx

(1100/RAJ/PBT)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अहिल्याबाई होल्कर का अपमान नहीं सहेंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, निधन संबंधी उल्लेख करना है, प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अत्यंत दु:ख के साथ, मुझे सभा के हमारे पूर्व साथी श्री सुरूप सिंह हिर्या नाइक के निधन के बारे में सूचित करना है। वे महाराष्ट्र के नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री नाइक 8 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान सभा के माननीय सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र विधान सभा के माननीय सदस्य भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।

श्री सुरूप सिंह हिर्या नाइक का निधन 24 दिसम्बर, 2025 को 87 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के नंदुरबार में हुआ।

यह सभा श्री सुरूप सिंह हिर्या नाइक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ॐ शांति: शांति: शांति:।

…(व्यवधान)

1102 बजे

(इस समय श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री गुरजीत सिंह औजला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

(प्रश्न 41)

*SHRI APPALANAIDU KALISETTI (VIZIANAGARAM): Every year youth from North Andhra, particularly from Vizianagaram and Srikakulam districts, join BSF and CAPFs. But due to lack of facilities and infrastructure aspirants have to travel long distances for application assistance, physical preparation and initial guidance.

I would like to know whether the Government has any proposal to set up a pre-recruitment training and facilitation centre in my constituency. Also, I would like to know whether the Government is considering the feasibility of setting up a training centre in my constituency.

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में सीएपीएफ का एक प्रशिक्षण संस्थान है। तत्काल विजयनगरम में सीएपीएफ का कोई प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है, विचार नहीं है।...(व्यवधान) हम प्रशिक्षण बड़ी तत्परता से देते हैं।...(व्यवधान) देश के विभिन्न क्षेत्रों में 83 प्रशिक्षण केन्द्र हैं।...(व्यवधान) हम वहां परंपरागत और आधुनिकता के साथ प्रशिक्षण देते हैं।...(व्यवधान) हम वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य को दृष्टिकोण में रखते हुए प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण का परिणाम यह है कि आज देश से नक्सलवाद, वामपंथी और उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है।...(व्यवधान)

(1105/NK/SNT)

महोदय, मार्च तक वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में सफलता मिली है। हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में कामयाब हो रहे हैं। ... (व्यवधान) आज नार्थ ईस्ट में शांति बहाल है, ... (व्यवधान) हम चुनाव प्रबंधन में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जब जरूरत होती है तो हम राज्यों का भी सहयोग करते हैं। धन्यवाद।

*SHRI APPALANAIDU KALISETTI (VIZIANAGARAM): CAPF officers are now considered as organised Group A services and enjoy similar entitlements and career progression like other organised Group A services. Sir, over the years there are concerns about slow promotions and a limited number of senior posts. The honourable Supreme Court has taken cognizance of the matter and in May 2025 directed the authorities for a comprehensive cadre review of all Central Armed Police Forces to be completed within six months.

I would like to know from the hon. Minister about the status of the cadre review and the date by which the orders of the Supreme Court will be implemented.

---

* Original in Telugu

(pp. 3-30)

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, सीएपीएफ में प्रमोशन एक सतत् प्रक्रिया है, हम प्रमोशन की हमेशा समीक्षा भी करते हैं, … (व्यवधान) हम समय-समय पर प्रमोशन भी देते रहते हैं। जहां तक सीएपीएफ में प्रमोशन के तथ्यों को उजागर करने की बात माननीय सदस्य ने कही है। … (व्यवधान) प्रमोशन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल में नियोजित तरीके से वेल में आकर नारेबाजी करने का कोई तर्क है? प्रश्न काल माननीय सदस्यों का होता है, उसमें माननीय सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही तय होती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्रश्न काल में नियोजित तरीके से सदन के अंदर नारेबाजी करते है, क्या यह उचित है? आप सदन चलने दें, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, बजट पर चर्चा होगी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त मौका मिलेगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं, आप नारेबाजी और हंगामा करना ही चाहते हैं तो सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1109 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/KDS/RTU)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति : आइटम नंबर 3, श्री जितिन प्रसाद जी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

———

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Respected Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(1) Review by the Government of the working of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2024-2025.

(2) Annual Report of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

———

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ.90(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1971 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.91(अ) जो दिनांक 6 जनवरी, 2026 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.6028(अ) जो दिनांक 26 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ.79 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

———

माननीय सभापति : आप कृपया बैठिए। कोई भी एग्जीबिट दिखाना गलत है। आपको मौका मिलेगा। Kindly be seated. Please sit down.

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है। उसके बाद आपको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 6, डॉक्टर पी. चन्द्रशेखर जी।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DR. CHANDRA SEKHAR PEMMASANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Rural Livelihoods Promotion Society, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Rural Livelihoods Promotion Society, New Delhi, for the year 2024-2025.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF), New Delhi, for the year 2024-2025.

———

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और दिव्याङ्गजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इम्फाल गार्डियन सोसाइटी, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इम्फाल गार्डियन सोसाइटी, इम्फाल पश्चिम जिला, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) परिवर्तन स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इंपेयर्ड (परिवर्तन इंटीग्रेटेड रुरल वेलफेयर सोसाइटी),एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिवर्तन स्पेशल स्कूल फॉर हियरिंग इंपेयर्ड (परिवर्तन इंटीग्रेटेड रुरल वेलफेयर सोसाइटी), एलुरु जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) वृन्दावन शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वृन्दावन शिक्षा एवं जन कल्याण समिति, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड, बिष्णुपुर, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड, बिष्णुपुर, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) जॉनसन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उन्नाव के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) जॉनसन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, उन्नाव के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) दृष्टिबाधित आवासीय विद्यालय, गढ़वाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दृष्टिबाधित आवासीय विद्यालय, गढ़वाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, दानकग्रे, वेस्ट गारो हिल्स, तुरा, मेघालय के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन, दानकग्रे, वेस्ट गारो हिल्स, तुरा, मेघालय के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) शांतिनिलयम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिनिलयम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

———

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL (SHRI BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the Rashtriya Ispat Nigam Limited, Visakhapatnam, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Bridge and Roof Co. (India) Limited and the Ministry of Heavy Industries for the year 2025-2026.

———

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): Sir, with your permission, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL), Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL), Mumbai, for the year 2024-2025.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2024-2025.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cotton Textiles Export Promotion Council of India (TEXPROCIL), Mumbai, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cotton Textiles Export Promotion Council of India (TEXPROCIL), Mumbai, for the year 2024-2025.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2024-2025.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Jute Industries' Research Association, Kolkata, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Jute Industries' Research Association, Kolkata, for the year 2024-2025.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2024-2025.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(13) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Handloom Development Corporation Limited, Noida, for the year 2024-2025.

(ii) Annual Report of the National Handloom Development Corporation Limited, Noida, for the year 2024-2025, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(15) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 13B of the Central Silk Board Act, 1948: -

(i) S.O.6140(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2025 nominating Mrs. Guha Poonam Tapas Kumar, IAS, Commissioner-cum-Secretary, Handlooms, Textiles & Handicrafts Departments, Government of Odisha, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the Central Silk Board Act, 1948.

(ii) S.O.169(E) published in Gazette of India dated 12th January, 2026 nominating Shri Narayanasa K. Bhandage, Member of Rajya Sabha, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years w.e.f. 18th December, 2025 or till completion of his term in Rajya Sabha, whichever is earlier,

subject to other provisions of the Central Silk Board Act, 1948.

(iii) S.O.350(E) published in Gazette of India dated 22nd January, 2026 nominating two members, mentioned therein, to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification, subject to the provisions of the Central Silk Board Act, 1948.

(16) A copy of the Notification No. S.O. 6138(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st December, 2025 making certain amendments in Notification No. S.O. 1830(E) dated 22st April, 2025 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987.

———

समितियों के लिए निर्वाचन/ नाम-निर्देशन

(i) प्राक्कलन समिति

1204 बजे

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 311के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

———

(ii) Committee on Public Accounts

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): I wish to move the following:-

"That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (1) of Rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, fifteen members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May, 2026 and ending on the 30th April, 2027."

(1205/AK/CS)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

… (व्यवधान)

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): I rise to move the following:-

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st May, 2026 and ending on the 30th April, 2027 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

… (व्यवधान)

(iii) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें। "

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

… (व्यवधान)

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

… (व्यवधान)

(iv) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंध समिति

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

.....

(1210/RV/SRG)

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2026 से आरंभ और 30 अप्रैल, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

MOTION RE: 14th REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I rise to move the following:-

"That this House do agree with the Fourteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 2nd February, 2026."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 2 फरवरी, 2026 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, आप लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let the House go on.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, पहले आप लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. Let the proceedings of the House go on.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, पहली बात तो यह है कि आप इस तरह एग्जिबिट्स को हाउस में नहीं ला सकते हैं। ऐसे एग्जिबिट्स को एग्जिबिट नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि यह नियम के खिलाफ है। बार-बार आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह नियम के खिलाफ है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : धर्मेन्द्र जी, आप एग्जिबिट्स को नीचे कीजिए, फिर बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1213 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/SRG/MY)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1400 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अपने मामले के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

Re: Need to take comprehensive measures to control drug addiction cases in Karnataka and other parts of country

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR): The recent data reveals a staggering 63% surge in drug-related cases, rising from 4,188 in 2024 to 6,824 in 2025 in Karnataka. This sharp increase is accompanied by a 60% spike in cases registered against drug users, signaling a shift in enforcement strategy that reflects the growing ubiquity of substance abuse across the state. A large number of students and youth unknowingly fall prey to this drug racket. The problem is further complicated by the use of anonymous digital platforms. The social ramifications are devastating, as addiction frequently leads to the fragmentation of family units, domestic violence, and a rise in related crimes such as theft and violent outbursts. To address this, a unified response is essential. There must be seamless coordination between the State Anti-Narcotics Task Force, the Narcotics Control Bureau, and the Foreigners Regional Registration Office to disrupt supply chains and manage the rising involvement of foreign nationals. Simultaneously, we should expand community-driven rehabilitation and de-addiction infrastructure, ensuring that enforcement is balanced with a humanitarian focus on recovery to reclaim the state's future from this growing threat. Massive education programs have to be held at school and college levels. I request the Government to urgently intervene.

(ends)

Re: Need to provide stoppage of trains at railway stations in Hazaribagh and Ramgarh districts in Jharkhand

श्री मनीष जायसवाल (हज़ारीबाग) : मैं सदन का ध्यान झारखण्ड राज्य के हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों की ओर आकृष्ट कराना चाहता/चाहती हूँ, जहाँ के कई छोटे किंतु महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से वंचित हैं। विशेष रूप से हजारीबाग रोड, बरही, चौपारण, केरेडारी, रामगढ़ कैंट, बरकाकाना एवं गोला रोड जैसे स्टेशनों पर सीमित ठहराव के कारण यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इन स्टेशनों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी, मरीज, श्रमिक एवं व्यवसायी यात्रा करते हैं, किंतु एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के अभाव में उन्हें दूरस्थ बड़े स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे समय, धन एवं संसाधनों की हानि होती है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त स्टेशनों पर उपयुक्त एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की व्यवहार्यता का शीघ्र परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जाए, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को सुलभ एवं सुरक्षित रेल सुविधा उपलब्ध हो सके।

(इति)

Re: Need to develop Shringverpur Dham in Prayagraj district, Uttar Pradesh as a gobal tourist destination

श्री प्रवीण पटेल (फूलपुर) : श्रृंगवेरपुर धाम रामायण काल का यह स्थल भगवान श्री राम और निषादराज गुह की अटूट मित्रता का प्रतीक है। यही वह स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम ने वनवास जाते समय गंगा नदी पार की थी। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद, यहाँ पर्यटन सुविधाओं का अपेक्षित विस्तार अभी भी शेष है। निम्नलिखित मांगें: रामायण सर्किट में प्रमुखता: श्रृंगवेरपुर धाम को स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के एक प्रमुख केंद्र के रूप में शामिल कर यहाँ बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार किया जाए। गंगा तट पर स्थित घाटों का पक्का निर्माण, आरती स्थल का आधुनिकीकरण और एक सुंदर रिवर फ्रंट विकसित किया जाए ताकि श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आकर्षित हो सकें। संग्रहालय और लाइट-एंड-साउंड शो: निषादराज गुह और श्री राम के प्रसंगों को दर्शाने वाला एक अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय और लाइट-एंड-साउंड शो शुरू किया जाए, जिससे नई पीढ़ी को अपनी विरासत की जानकारी मिल सके। परिवहन कनेक्टिविटी: श्रृंगवेरपुर को प्रयागराज शहर और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ने के लिए बेहतर सड़क मार्ग और नियमित परिवहन सेवाओं की व्यवस्था की जाए। निवेदन है कि श्रृंगवेरपुर धाम की ऐतिहासिकता और आस्था को सम्मान देते हुए इसे एक विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाय।

(इति)

Re: Need to sanction a special package to address severe air pollution in Rajahmundry, Andhra Pradesh

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): I wish to draw the attention of the Government to the severe air pollution in Rajahmundry and the structural disparity in funding under the National Clean Air Programme (NCAP). Despite Rajahmundry consistently recording PM10 levels (70–75 μg/m³) above national standards—often exceeding those of Vijayawada—it has received only ₹9.55 crore compared to Vijayawada's ₹130.35 crore. This 16-fold disparity exists because allocations currently rely on administrative classification rather than actual pollution severity. Rajahmundry has already utilised nearly 100% of its limited funds. This inadequacy is critical in view of the forthcoming Godavari Pushkaralu, expected to attract 8 crore pilgrims. The inevitable surge in diesel transport, generators, and road dust will drastically worsen the AQI, posing severe health risks to devotees. Furthermore, unlike Vijayawada, Rajahmundry has not been provided with scientific Source Apportionment studies to guide its planning. I urge the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to Sanction a Special Clean Air Package of ₹150 crore for Rajahmundry to implement dust suppression, traffic management, and emission controls specifically for the Pushkaralu; Commission scientific studies for the city; and Realign NCAP funding to be linked to pollution severity and mitigation requirements rather than population criteria alone. This is essential for environmental equity and public health.

(ends)

Re: Need to establish Defence Sector manufacturing units in Deoria, Uttar Pradesh

श्री शशांक मणि (देवरिया) : मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान देश में रक्षा विनिर्माण को कुछ सीमित शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रखने के बजाय उसे अधिक व्यापक और समावेशी बनाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा उत्पादन ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक तथा रक्षा निर्यात ₹ 23,000 करोड़ के स्तर तक पहुँचना सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों, घरेलू खरीद को प्राथमिकता और निजी क्षेत्र की भागीदारी ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर इस दृष्टिकोण के सशक्त उदाहरण हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर में ₹28,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना बनी है। अब आवश्यकता है कि इन नीतिगत प्रयासों का लाभ देवरिया जैसे गैर-महानगरीय जिलों तक भी पहुँचाया जाए, जहाँ भूमि, युवा कार्यबल और बेहतर होती कनेक्टिविटी उपलब्ध है। iDEX, TDF और डिफेन्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जैसी योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में सहायक रक्षा उद्योग विकसित किए जा सकते हैं। रक्षा विनिर्माण का विकेंद्रीकरण आर्थिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा। (इति)

Re: Need to amend the maintenance and welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 for appropriate protection of Senior citizens in the country

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I wish to draw the attention regarding abuse against senior citizens, a grave violation that undermines the very fabric of our society. Recent studies reveal that nearly 50% of elderly individuals endure emotional, physical, or financial exploitation, often at the hands of their own kin, with only a fraction reporting due to fear and dependency. This scourge not only inflicts irreparable harm but also erodes the dignity of our elders deserve after lifetimes of contribution to nation-building. In an ageing population projected to reach 20% by 2050, such neglect threatens social harmony and economic productivity, as traumatized seniors withdraw from community roles they once enriched. Our Government has championed the welfare of the vulnerable through flagship initiatives like the National Action Plan for Senior Citizens and Atal Vayoshree Yojana. Yet, the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, with its modest penalties, remains woefully inadequate against escalating violations. I urge an immediate amendment to impose stringent punishments, such as enhanced imprisonment up to seven years and hefty fines, to deter perpetrators. Furthermore, integrating Elderline helplines with local police for proactive interventions, alongside awareness campaigns in every panchayat, will fortify safeguards. (ends)

Re: Need to take comprehensive measures to achieve the objective of economic empowerment of farmers and sustainable farming through Carbon credits

SHRI RAO RAJENDRA SINGH (JAIPUR RURAL): In compliance with the global commitment of curbing Carbon Footprint, the Carbon Credits Trading System (CCTS) evolved by the Government of India in 2023 matches global best practices by controlling environmental deterioration through a market-based approach. As envisaged by the Kyoto Protocol (1997), Carbon markets allow corporations to purchase Carbon Credits from projects that mitigate emissions through various means, including afforestation, renewable energy, and methane capture. While private institutions have effectively utilised the instrument to empower agriculturalists through Carbon Credits, more is to be desired from the Government, as a stakeholder. While Carbon Credits are utilised in various facets of trade and business, their potential remains immense in ensuring the economic empowerment of Farmers while furthering the transition to more sustainable and diverse forms of farming. Given that the scheme comes as a systematic, exhaustive and elaborate evolution of the Perform, Achieve and Trade (PAT) Scheme formulated by the erstwhile UPA Government in 2012. It is important that particular emphasis is exercised in enhancing awareness, removing financial barriers and increasing accessibility for various stakeholders of the agricultural ecosystem, so that the twin objectives of economic empowerment of farmers and ensuring transition to sustainable farming are comprehensively achieved. (ends)

Re: Need to develop NH-89 (Ajmer to Nagaur via Merta) as a four lane road in Rajasthan

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-89, जो अजमेर से नागौर होते हुए मेड़ता मार्ग से गुजरता है, वर्तमान में अत्यधिक यातायात दबाव का सामना कर रहा है। यह मार्ग पश्चिमी एवं मध्य राजस्थान की एक प्रमुख जीवनरेखा है, जो औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। PWD एवं NHAI द्वारा किए गए नवीनतम ट्रैफिक सर्वे के अनुसार: - बाड़ी घाटी टोल प्लाजा पर प्रतिदिन यातायात लगभग 12,400 PCU (Passenger Car Unit) से अधिक दर्ज किया गया है। - बुटाटी टोल प्लाजा पर प्रतिदिन यातायात लगभग 10,400 PCU से अधिक पाया गया है। - जबकि MoRTH के मानकों के अनुसार 10,000 PCU से अधिक यातायात वाले मार्ग को फोर लेन में अपग्रेड हेतु योग्य माना जाता है। वर्तमान में यह मार्ग केवल दो लेन का है, जिससे पीक आवर्स में भारी जाम की स्थिति बनती है, सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, यात्रा समय एवं परिवहन लागत बढ़ रही है, व्यापार, पर्यटन एवं औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि NH-89 (अजमेर–नागौर via मेड़ता) मार्ग को फोर लेन कराये जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें | (इति)

Re: Need for a Standard Operating Procedure (SOP) for protection of trees during construction/widening of road projects in country

SHRI BALABHADRA MAJHI (NABARANGPUR): Large numbers of trees are required to be cut for any infrastructure project. It is inevitable and there is provision of compensatory reforestation. But, when it comes to road projects, especially those constructed in rural and semi-urban areas, there is a need to issue an SOP so that trees are not cut every time while there is need for widening of the road. It is not just tree cutting, services like water supply pipe lines, telecom cables, gas pipe lines, power supply lines etc are also required to be shifted every time when there is widening work. It costs money to the Government and inconvenience to the public. Widening can be only on one side of road, so that trees & facilities on the other side are saved. Wherever services are provided or trees planted, after the road is constructed, it should be at a sufficient distance to accommodate future widening. For new road, land acquisition should be wide enough to accommodate future widening and for services, including tree plantation. Most importantly, there should be a joint signature of officials of all concerned Departments. Any violation by anybody viz. the defaulting officials, contractors, general public should be taken seriously and penalized appropriately. (ends)

Re: Need to set up National Data Centres in Rajasthan

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I wish to draw the attention of the house towards the requirement of establishing National Data Centres in Rajasthan. While India generates 20% of the world's data, it has a mere 3% share in the world's data centre capacity. Additionally, the storage capacity of data centres owned by the National Informatics Centre (NIC) is 9.2 MW. The storage capacity of such data centres is minuscule compared to the 499 MW capacity of data centres owned by private industries. Under the visionary leadership of Prime Minister, Digital India has transformed e-governance, making public services far more transparent and accessible. With the growing volumes of data generated for facilitating e-governance, there is a pressing need to establish more National Data Centres to store sensitive Government data. I urge the Ministry of Electronics and Information Technology to facilitate the establishment of National Data Centres in Rajasthan. The state having the highest installed capacity for solar energy, has the potential to meet electricity demand of these data centres through renewable sources. This uninterrupted supply of electricity, coupled with abundant availability of land and skilled labour makes Rajasthan the ideal destination for setting up new National Data Centres. (ends)

Re: Need to adopt "Bha' footwear sizing system designed by Central Leather Research Institute in Indian footwear industry

डॉ. आनन्द कुमार गोंड (बहराइच) : मैं सरकार का ध्यान देश में मानकीकृत फुटवियर साइजिंग प्रणाली के अभाव से उत्पन्न एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता एवं उद्योगगत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्तमान में विभिन्न भारतीय व अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स द्वारा अलग-अलग साइजिंग मानकों के उपयोग के कारण उपभोक्ताओं को गलत फिटिंग, असुविधा, बार-बार जूते बदलने की मजबूरी तथा अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (CLRI) द्वारा भारतीय पैर संरचना पर आधारित वैज्ञानिक 'भ' (BHA) फुटवियर साइजिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जो भारतीय उपभोक्ताओं की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसके बावजूद, इस प्रणाली को उद्योग द्वारा व्यापक रूप से नहीं अपनाया गया है, जिससे इसके लाभ आम नागरिक तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि उपभोक्ता हित, "मेक इन इंडिया" तथा भारतीय फुटवियर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को ध्यान में रखते हुए 'भ' (BHA) फुटवियर साइजिंग सिस्टम को एक राष्ट्रीय मानक के रूप में अधिसूचित करने की नीति पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही, चरणबद्ध रूप से इसे सभी भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर ब्रांड्स के लिए अनिवार्य बनाने हेतु स्पष्ट रोडमैप एवं समयसीमा तय की जाए।

(इति)

Re: Need to construct Pit line at Chittorgarh Junction Railway Station in Rajasthan

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौडगढ का पश्चिम रेलवे के रतलाम मण्डल का अतिमहत्वपुर्ण स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन स्थित है। यहॉ से चारों दिशाओं में उदयपुर, अजमेर, कोटा, रतलाम के लिये रेलों का आवागमन होता हैं, इसके साथ ही यह मालगाड़ियों के लिये भी अतिमहत्वपूर्ण स्टेशन हैं। चित्तौड़गढ़ एक औद्योगिक एवं ऐतिहासिक नगरी हैं इस कारण से यहॉ लाखों पर्यटक आतें हैं। यहॉ के स्टेशन पर रेलवे की पीट लाईन के नही होने के कारण यहॉ से किसी गाड़ी को प्रारंभ करना व्यवहारिक नही हो पा रहा हैं। यहॉ के लिये भरपूर यात्री भार के पष्चात भी पीटलाईन के नही होने से वाशिगं व सफाई आदि के लिये कोई गाड़ी यहॉ से प्रारंभ या टर्मिनेट नही हो पाती हैं। अतः इस संबध में मेरा आपसे अनुरोध हैं कि चित्तौड़गढ़ जं. रेलवे स्टेशन पर पीट लाईन का निर्माण करवाया जाये जिससे यहॉ से अन्य रेलगाड़ीयों के प्रारंभ होने की राह प्रशस्त हो पाये।

(इति)

Re: Need for investigation into alleged religious intolerance shown against Christian minority in different parts of country

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I am deeply disturbed by the rising tide of reported violence and intimidation against Indian Christian minority, which undermines the constitutional pillars of religious freedom, equality, and dignity. This orchestrated campaign of hatred threatens the pluralistic fabric of our nation, transforming festive occasions into arenas of fear. Recent Christmas incidents highlight this grim pattern. In Lajpat Nagar of Delhi, right-wing groups verbally assaulted women and children wearing Santa hats. In Chhattisgarh, mobs attacked churches and homes in Kanker, assaulted nuns in Durg, vandalized decorations in Raipur Mall, and banned Christian pastors from villages. Madhya Pradesh saw disruptions at a prayer meeting in Jabalpur Gorakhpur, attended by disabled children. In Ghaziabad of Uttar Pradesh, a Christmas Eve service was interrupted. Even Kerala witnessed an attack on children caroling in Palakkad, with instruments destroyed. These acts, far from isolated, reveal systemic intolerance. The silence of Government emboldens perpetrators, contradicting "Sabka Saath, Sabka Vikas." As New Year approached, similar moral policing occurred. I urge immediate Government intervention to investigate these outrages, enforce strict precautions, and safeguard citizens right to practice their faith without fear. (ends)

Re: Stoppage of trains at Sonepat Railway Junction, Haryana

श्री सतपाल ब्रह्मचारी (सोनीपत) : सोनीपत जंक्शन पर निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव किया जाए:-

1. गाड़ी संख्या 22429-दिल्ली-पठानकोट एक्सप्रेस
2. गाड़ी संख्या 20807/20808-हीराकुंड एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
3. गाड़ी संख्या 22455/22456-साईनगर शिरडी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
4. ट्रेन न. 11905/11906,12715/12716,12445/12446 तथा 12413/12414

यह भी अवगत कराना है कि उत्तर रेलवे की उपरोक्त संस्तुतिया वर्तमान में रेलवे बोर्ड के सबंधित कोचिंग निदेशालय में विधाराधीन है। सोनीपत एवं आसपास के क्षेत्र की जनता की दीर्घकालिक और जनहित से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए आपसे विन्रम अनुरोध है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान कर उक्त संस्तुतियों की शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे क्षेत्र के यात्रियों, विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं तीर्थयात्रियों को विशेष लाभ मिल सके। हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में सोनीपत–गोहाना के बीच बिछाई जा रही/बिछ चुकी ब्रॉड गेज (बीजी) रेलवे लाइन के कारण उत्पन्न एक गंभीर स्थानीय समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उक्त रेलवे लाइन के निर्माण के कारण हुल्लाहेरी एवं खिजरपुर जाट माजरा गांवों की कृषि भूमि के बीच पारंपरिक आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। सोनीपत–गोहाना बीजी रेलवे लाइन के अंतर्गत हुल्लाहेरी एवं खिजरपुर जाट माजरा गांवों की कृषि भूमि के बीच संपर्क पुनः स्थापित करने हेतु शीघ्र सबवे/अंडरपास के निर्माण का प्रावधान किया जाए। (इति)

Re: Need to ensure full implementation of provision of 74th constitutional amendment in Uttar Pradesh

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : भारतीय संविधान अनुच्छेद 368 के अंर्तगत संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 द्वारा भाग 9-क अनुच्छेद 243'त' से 243'ह' भारत देश के नगरों में लोकतांत्रिक प्रणाली सुदृढ़ करने के लिये 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्णतया लागू नही किया गया जबकि अन्य प्रदेशों में लागू है। जिसके कारण नगर निकायों के महापौर/अध्यक्षों, पार्षदों/सभासदों आदि को जनप्रतिनिधि का दर्जा प्राप्त नही है और वेतन यात्रा-भत्ता भी नही है और वेतन यात्रा-भत्ता भी नही मिलता। अतः अन्य राज्यों की तरह उ0प्र0 के नगर निकायों को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिये 74वां संविधान संशोधन पूर्णतः एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाय।

(इति)

Re: Status of proposed delimitation exercise in 2026 and possible operationalization of reservation of seats for women, SC and ST

ADV. GOWAAL KAGADA PADAVI (NANDURBAR): I seek to raise this matter under Rule 377 regarding the proposed delimitation exercise and its impact on tribal areas, Maharashtra, and Nandurbar Parliamentary Constituency. This notice examines its linkage with the forthcoming Census and implementation of the Women's Reservation Act. The Government is requested to clarify the process through which the Delimitation Act and exercise will be introduced, in view of the constitutional freeze on delimitation until the first Census conducted after 2026. It may specify whether the next delimitation will be based on the upcoming Census and the tentative timeline for completing the process. Further, details are sought regarding the constitutional and administrative procedure for constituting the Delimitation Commission, including its composition, powers and safeguards to ensure transparency. The Government should explain how delimitation will affect the number of Lok Sabha and Assembly constituencies. Specific information is required on the impact of delimitation on Scheduled

Areas and tribal-dominated regions, Nandurbar, and whether safeguards will prevent under-representation of tribal communities. The Government should clarify if any reduction or alteration of reserved Scheduled Tribe constituencies is anticipated. The House may be informed about changes to constituency boundaries and reservation status for SC and ST seats. Details are sought on operationalising the Women's Reservation Act and the rotation of women-reserved seats without disturbing existing SC and ST reservations. Finally, the Government may state whether consultations have been held with tribal representatives.

(ends)

Re: Need to expedite construction of Singhana-Titanward Road under NH-311 in Jhunjhunu Parliamentary Constituency

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 311 पर सिंघाना–टीटनवाड़ (उदयपुरवाटी) मार्ग के निर्माण कार्य में हो रही देरी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनूं में NH-311 के अंतर्गत सिंघाना–खरकड़ा–जसरापुर–नानूवाली बावड़ी–केड़–टीटनवाड़ (उदयपुरवाटी) सड़क का कार्य लंबे समय से प्रस्तावित है। इस महत्वपूर्ण मार्ग को काफी पहले मंजूरी एवं स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परंतु इसके बावजूद आज तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इस मार्ग पर दैनिक यातायात का भारी दबाव रहता है, और सड़क निर्माण में हो रही देरी से आमजन, किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा एम्बुलेंस/आपातकालीन सेवाओं को निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि इस स्वीकृत मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य को अविलंब प्रारंभ कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र राहत मिल सके।

(इति)

Re: Need to provide reservation to ex-servicemen in Group 'A' & 'B' posts

श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर (सलेमपुर) : देश सेवारत सैनिको के मनोबल तथा पूर्व सैनिकों के सम्मान एवं पुनर्वास अवसरों की दयनीय स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सेना को युवा बनाए रखने हेतु प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सैनिक अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं, जिनमें लगभग 12,000 केवल उत्तर प्रदेश से होते हैं। ये सैनिक 33 से 45 वर्ष की आयु में ही घर लौट आते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को केवल समूह 'ग' के कुछ पदों चपरासी, सफाईकर्मी, रेलवे गैंगमैन, ट्रैकमैन आदि—में ही आरक्षण प्रदान किया जाता है, जो उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन को सभी समूहों में संवैधानिक आरक्षण प्राप्त है, वहीं भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण केवल कार्यकारी आदेशों तक सीमित है। पूर्व सैनिकों के सामाजिक सम्मान के विपरीत है, बल्कि सेवारत सैनिकों के मनोबल को भी प्रभावित करता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानजनक पुनर्वास हेतु समूह 'क' एवं 'ख' पदों में भी आरक्षण प्रदान करें।

(इति)

Re: Need to establish a Commission for conservation and protection of Cows

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र आंवला सहित उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में गौवंश सड़कों पर आवारा छुट्टा पशु के रूप में परेशान हो रहा है। जहाँ जहाँ गोवंश संरक्षण केंद्र गौशाला बनाए गए हैं वहाँ पर भी हमारी गाय माता भूखो तड़प कर मर रही है व इस कारण से हमारे अन्नदाता किसान भाई भी दुखी व परेशान हैं। अभी हाल ही में मेरे क्षेत्र आंवला में गौशाला के अंदर भूख और बीमारी के कारण लगभग 25 गाय मर गई, जो दुखद है इसको लेकर वहाँ के किसानों में बहुत आक्रोश है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि पूरे देश के लिए एक गौवंश संरक्षण आयोग बनाया जाए जो इस समस्या का निवारण करे और किसान भाइयों की इस बड़ी समस्या का समाधान भी कराएं।

(इति)

Re: Need to comply with Provisions of compulsory Jute packaging laws and to restore the procurement under Jute packaging material Act in West Bengal and other parts of country

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): The jute industry in West Bengal, employing over 2.5 lakh workers and supporting millions of dependent families, is in severe socio-economic distress. Once sustained by guaranteed government procurement under the Jute Packaging Materials Act, the industry has seen orders slashed and synthetic alternatives permitted, weakening demand for traditional jute sacks. Recent approvals for non-jute bags in key procurement schemes have directly undercut jute demand, deepening the crisis faced by mills and workers. This policy shift has contributed to mill closures and widespread unemployment. Workers confront irregular wages, precarious employment, and loss of livelihood, with entire families pushed into economic insecurity. Despite environmental rhetoric against plastics, inconsistent enforcement of mandatory jute use and growing tolerance for plastic alternatives have eroded the industry's market base, compounding its long-standing structural problems. The result is poverty, joblessness, and deteriorating living conditions for jute workers in Bengal. We demand that the Central Government mandate full compliance with compulsory jute packaging laws and restore assured procurement to protect workers and the industry.

(ends)

Re: Need for construction of a subway on Salem-Omalur railway line near Jagir Reddipatti in Salem Parliamentary Constituency

SHRI T. M. SELVAGANAPATHI (SALEM): It has been a long pending demand of the people of Arunthathiyar Colony, Chinna Mottur, Near Jagir Ammapalayam, Salem for construction of a subway, adjacent to a burial ground near Jagir Reddipatti, Salem in between Salem-Omalur Railway line, Southern Railway. This issue was taken up many times as the people of the area are facing very hardship to cross the railway line for various purposes. Finally, it was agreed by Railways to construct a subway near to the demanded place and were trying to identify a suitable location for the construction of the subway to redress the grievances of people to cross to the other side of the railway track. However, the issue has not moved further as it seems the Railways has not taken any steps in this regard. This area comes under my Parliamentary Constituency, Salem. Therefore, I urge upon the honourable Minister of Railway to direct concerned to immediately construct a subway at above place urgently, so that the problems being faced by the people of the area can be resolved. I shall be highly grateful if you could look into it and please make sure that the dream of the people of the area comes true.

(ends)

Re: Need to expedite tender process and construction of ESI hospital in Nellore Parliamentary Constituency

SHRI PRABHAKAR REDDY VEMIREDDY (NELLORE): Ministry of Labour & Employment approved to set up 100-bedded ESI hospital in my Nellore Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh in March, 2019, to provide primary, secondary and tertiary care medical services, including preventive, promotive, curative and rehabilitative services, to ESI beneficiaries and their dependents. After a lot of efforts, land acquisition for this hospital was completed by GoAP and an additional 1 acre land has also been acquired and earmarked for staff quarters. This information was given to concerned officials in the Ministry and the competent authority also approved the same. Now, the process of issuing tender, selecting bidder and starting construction of hospital is pending. The workers and their family members are eagerly waiting for the hospital to come up. Hence, I appeal to the Hon'ble Minister of Labour and Employment to kindly look into the issue and ensure completion of tender process and construction of hospital.

(ends)

Re: Need to enhance medical insurance & facilities to the victims of road accidents

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई 'कैशलेस ट्रीटमेंट' की संवेदनशील योजना के लिए सरकार की सराहना करता हूँ। यह 'गोल्डन ऑवर' में उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।एम्स (AIIMS) और अन्य बड़े अस्पतालों के आंकड़े बताते हैं कि 'ब्रेन इंजरी' (मस्तिष्क की चोट) और 'रीढ़ की हड्डी' की चोटों में मरीज को खतरे से बाहर आने में औसतन 18 से 25 दिनों तक आईसीयू (ICU) की आवश्यकता होती है। वर्तमान योजना में निर्धारित7दिनों की अधिकतम सीमा ऐसे अति-गंभीर मामलों में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है।7 दिन बीतते ही गरीब परिवार के लिए निजी अस्पतालों का भारी खर्च उठाना असंभव हो जाता है, जिससे मरीज की जान फिर जोखिम में पड़ जाती है और योजना का मूल उद्देश्य अधूरा रह जाता है। अतः मैं सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तत्काल कुछ सुधार किए जाएं। सर्वप्रथम, मस्तिष्क और रीढ़ की गंभीर चोटों की प्रकृति को देखते हुए 7 दिनों की आईसीयू समय-सीमा को बढ़ाकर चिकित्सकीय आवश्यकतानुसार या कम से कम 25 दिन किया जाए और वर्तमान चिकित्सा महंगाई को देखते हुए कवरेज की राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए।

(इति)

Re: Need to construct RoB on NH-322 in Samastipur district in Bihar as a four lane bridge

श्रीमती शांभवी (समस्तीपुर) : मैं सरकार का ध्यान बिहार के समस्तीपुर जिले में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-322 (NH-322) पर व्याप्त गंभीर यातायात समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस राजमार्ग के किलोमीटर 67 पर स्थित पुराना रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) केवल टू-लेन (Two-lane) है, जबकि इसके जुड़ने वाली दोनों ओर की सड़कें फोर-लेन (Four-lane) हैं।यह हाजीपुर और दरभंगा को जोड़ने वाला सबसे कम दूरी का और अत्यंत व्यस्त मार्ग है।इस स्थान पर घनी आबादी और बाजार होने के कारण, तथा भारी वाहनों के आवागमन से यहाँ हमेशा भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है,जिससे आम जनता त्रस्त है।विदित हो कि बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्र (दिनांक 24.03.2025) के माध्यम से इस पुराने पुल के समानांतर एक नए फोर-लेन आरओबी के निर्माण के अध्ययन के लिए 'डीपीआर कंसल्टेंट' (DPR Consultant) नियुक्त करने की अनुमति मांगी है। मेरा माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि जनहित को देखते हुए, NH-322 के 67वें किलोमीटर पर अतिरिक्त 'फोर-लेन आरओबी' के निर्माण हेतु डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी प्रदान करने की कृपा करें, ताकि इस महत्वपूर्ण मार्ग को जाम से मुक्ति मिल सके।

(इति)

Re: Need to expedite the construction of roads in Kaimur district, Bihar under Bharatmala Project

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : मैं सरकार का ध्यान बिहार के कैमूर जिले में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 119 किमी. भूमि अधिग्रहण एवं सड़क निर्माण की प्रगति के अंतर्गत पैकेज- I (19.24 किमी., 46.74 हे.), पैकेज- II (85.30 किमी., 11.24 हे.) एवं पैकेज- I (16.4 किमी., 8 भूखंड), पैकेज- II (1.64 किमी.,2 भूखंड) एवं पैकेज- III (29.42 किमी.) सहित कुल 119 किमी. सड़क का निर्माण प्रस्तावित/ निर्माणधीन है। भूमि अधिग्रहण में प्रगति के बावजूद निर्माण कार्य धीमा है तथा किसानों के शेष मुआवजा एवं आबरीट्रेशन के मामले लंबित है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि उपर्युक्त परियोजना में पैकेज-वार भूमि अधिग्रहण, भूमि हस्तांतरण एवं निर्माण कार्य की अधतन वर्तमान स्थिति एवं निर्माण में विलंब के प्रमुख कारण एवं शेष मुआवजा भुगतान एवं आर्बिट्रेशन मामलों के निपटारे की समय-सीमा बतावें एवं परियोजना की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने का कार्य करें।

(इति)

Re: Need to review the decision to develop new Greenfield Express Highways in Rajasthan

श्री अमरा राम (सीकर) : राजस्थान में 9 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बजट घोषणा के अनुसार डीपीआर बनाई जा रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा टोल बूथ है तथा सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, डीजल हैं जनहित को देखते हुए हाईवे बनाएं जाए लेकिन ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनाए जाए क्योंकि अगर हाईवे का निर्माण होगा तो मार्ग पर होटल, दुकान , व्यापार विकसित होगा और आमजन को रोजगार प्राप्त होगा तथा इलाके का विकास ओर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा तथा औद्यौगिक विकास की भी संभावना बनेगी। उदाहरणार्थ कोटपूतली से किशनगढ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 हैं और अब सरकार द्वारा कोटपुतली से किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने का क्या औचित्य है जबकि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रैसवे बनाने का तो औचित्य है।कोटपुतली से किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जिसमें 1669 हेक्टर भूमि अधिग्रहित की जाएगी जिसमें किसानों के खेत के बीच से हाईवे गुजरेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा और वह दो भागों में विभाजित भूमि में कोई विकास नहीं कर पायेगा क्योंकि ग्रीनफील्ड हाईवे जो 100 मीटर चौड़ा और 15 फीट ऊंचा मार्ग हें जिस पर केवल कंपनी के ही डेवलपमेंट जैसे होटल, पेट्रोल डीजल पंप होंगे इनके अलावा कोई भी अपनी दुकान भी नहीं रख सकता है जो कि केवल कंपनियों को फायदा करने का कार्य करेगा।

(इति)

Re: Incident of disrespect shown on the occasion of installation of statue of Dr. Bhimrao Ambedkar in Gwalior, Madhya Pradesh

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापना के विरोध में उनके चित्र और पुतले को सार्वजनिक रूप से जलाया गया, जातीय एवं सामाजिक विद्वेष फैलाया गया, और संविधान निर्माता का खुलेआम कई बार अपमान किया गया। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, यह राजनीतिक इच्छाशक्ति की विफलता है। क्या संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब का अपमान राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक शांति से जुड़ा विषय नहीं है? जब धार्मिक या सामाजिक विद्वेष फैलाने के मामलों में अन्य स्थानों पर NSA जैसे कठोर कानून लगाए जाते हैं, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या यह तथ्य नहीं है कि बहुजन समाज के महापुरुष के अपमान के मामलों में कानून का रवैया नरम दिखाई देता है? क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जवाबदेही तय करेगी और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब करेगी? इस घटना की उच्चस्तरीय समीक्षा कराई जाए, यह स्पष्ट किया जाए कि NSA क्यों नहीं लगाया गया, और यह सुनिश्चित किया जाए कि परम पूज्य बाबा साहेब के अपमान और सामाजिक नफरत फैलाने वालों को किसी भी स्तर पर संरक्षण न मिले।

(इति)

Re: Need to set up Damodar Valley Corporation headquarters in Jharkhand

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : दामोदर घाटी निगम की अधिकांश परिचालन एवं उत्पादन गतिविधियाँ झारखंड राज्य में केंद्रित हैं। निगम के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र जैसे बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन,कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन तथा अन्य इकाइयाँ झारखंड में स्थित हैं। इसके साथ ही मैथन एवं पंचेत जैसे महत्वपूर्ण बांध और जलाशय भी इस क्षेत्र में अवस्थित हैं। बड़ी संख्या में कोयला संसाधन,भूमि अधिग्रहण क्षेत्र तथा हजारों परियोजना-प्रभावित परिवार झारखंड में ही हैं। DVC का लगभग 75% प्रतिशत कमांड एरिया झारखंड में है, जिससे स्पष्ट है कि निगम का प्रमुख संचालन, प्रभाव एवं लाभ क्षेत्र झारखंड ही है। इसके बावजूद निगम का मुख्यालय झारखंड के बाहर स्थित है, जो व्यावहारिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। मुख्यालय राज्य के बाहर होने के कारण स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार एवं परियोजना क्षेत्रों के साथ समन्वय में विलंब, निर्णय लेने में कठिनाई तथा जनसमस्याओं के समाधान में देरी होती है। यदि मुख्यालय झारखंड में स्थापित किया जाता है तो इससे परियोजनाओं की निगरानी एवं क्रियान्वयन में तेजी आएगी, परियोजना-प्रभावित परिवारों एवं स्थानीय जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा, प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय झारखंड में स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएँ।

(इति)

माननीय सभापति: आइटम नंबर 19, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।

माननीय श्री राहुल गांधी जी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव -- जारी

1401 बजे

विपक्ष के नेता (श्री राहुल गांधी) : ऑनरेबल चेयरमैन, कल मैंने इस आर्टिकल पर अपना भाषण शुरू किया था। स्पीकर ने कहा था कि इसे रूल के मुताबिक किया जाए। अब मैं चाहता हूं कि यह जो आर्टिकल है, इसे ऑथेंटिकेट किया जाए। आप इसे ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पर बात करना चाहता हूं। इसे मैं आपको दे रहा हूं। … (व्यवधान) मैंने दिया है। मैं यही कर रहा हूं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please table it. We will examine it and get back to you.

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, I have authenticated the article.

HON. CHAIRPERSON: Please continue your speech on Motion of Thanks on President's Address.

SHRI RAHUL GANDHI: As I said yesterday, a very important matter in the President's Speech is the matter of national security and the relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the hon. President.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting LOP to please restrict himself to the speech of the hon. President.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today also, I have requested both Venugopal ji and Gaurav ji. We are patiently waiting to listen to the hon. Leader of the Opposition on the matter which was referred to just now, yesterday, the Chair had given a ruling on the paper which he has authenticated and which has been tabled in the House. But what I am saying is, when a ruling has already been given on a matter which he referred to yesterday, he cannot quote the same matter again on the pretext of making a reference indirectly. He cannot refer to the same matter.

Please continue with your speech. We are waiting. … (*Interruptions*) But please avoid referring to a matter which has been settled. … (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, hon. Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called on us, me and Gaurav Gogoi. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: When hon. LOP is standing, you are speaking.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I want to give a clarification. … (*Interruptions*) Please allow me to give a clarification. … (*Interruptions*) Please allow me to speak. … (*Interruptions*)

(1405/SM/MLC)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): Hon. LOP is standing and you are speaking.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please allow him to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): One minute, Sir. I want to give a clarification. The Parliamentary Affairs Minister has taken my name… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please allow him to speak. He has already started his speech.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Yesterday, hon. Speaker's ruling was not to quote the book. This was the only ruling. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, Sir. He has already started speaking. Let him continue.

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I need to make a clarification because the Parliament Affairs Minister has taken my name.

HON. CHAIRPERSON: Do you want him to speak or not?

… (*Interruptions*)

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Does this House belong to them only? Does this House not belong to us?

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): What is this *yaar*? Why are you saying this? He has taken his name.

HON. CHAIRPERSON: Venugopal ji, kindly be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No. Please listen to me. What did you say just now? What do you mean by *yaar*?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This is Parliament of India. You cannot address the Chair by saying *yaar*. What is this?

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You cannot address the Chair by saying *yaar*.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please take back your word. You cannot address the Chair by saying *yaar*.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. LOP is standing. Please allow him to speak. You are not allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी आप बोलिएगा।

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please allow him to speak.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please allow him to speak.

… (*Interruptions*)

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग (लुधियाना) : चेयरमैन सर, यार कह दिया, तो क्या हो गया, क्या कोई आफत आ गई है?… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, it is not correct.

(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON:There should be decorum in the House. You should respect the Chair. You should know how to behave in the House.

(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, it is not correct.

Hon. Rahul ji, please continue to speak.

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, if the issue is my quoting a magazine which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. LOP, Rahul Gandhi ji, please listen to me. You have been given permission to speak on the President's Address.

SHRI RAHUL GANDHI: I am speaking on the President's Address.

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

HON. CHAIRPERSON: Please allow him to speak. What is this? Yesterday, hon. Speaker has given a ruling.

SHRI RAHUL GANDHI: Sir, it is not a permission that I am being given … (*Interruptions*) I am the Leader of Opposition of this country… (*Interruptions*) You are not giving me permission… (*Interruptions*) It is my right… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Speaker has already given a ruling under Rule 349.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: If you do not want LOP to speak, I will have to give opportunity to others to speak.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am giving him the opportunity. ये नहीं चलेगा। Hon. LOP can speak. He does not require your support.

(1410/GM/GG)

SHRI RAHUL GANDHI: Hon. Chairperson, our President's Address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. … (*Interruptions*) This is central to our President's Address. This is central, as you have seen, to our Budget. All I am saying is that I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped?

Sir, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. … (*Interruptions*)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : सर, ये बार-बार भारतीय सेना का अपमान करने का काम करते हैं। … (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, what is this? Will you give a ruling now?… (*Interruptions*)

1412 hours

(At this stage, Shri Shafi Parambil and Shrimati Sanjna Jatav came and stood near the Table)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KRISHNA PRASAD TENNETI): I repeatedly requested the hon. Leader of Opposition to speak on the President's Address.

… (*Interruptions*)

1412 hours

(At this stage, Shri Shafi Parambil and Shrimati Sanjna Jatav went back to their seats.)

माननीय सभापति : माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I made repeated requests to the hon. Leader of Opposition to speak on the President's Address.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलना नहीं चाहते हैं?

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Satabdi Roy Banerjee.

SHRIMATI SATABDI ROY BANERJEE (BIRBHUM): I do not want to speak.

HON. CHAIRPERSON: Shri D.M. Kathir Anand.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri G.M. Harish Balyogi.

… (*Interruptions*)

1413 hours

(At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Imran Masood and some other Members came and stood near the Table)

TEXT OF AMENDMENTS

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

1. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूर्णिया में पटना उच्च न्यायालय की दूसरी बेंच बनाने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

2. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रेल परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए समयसीमा निर्धारित किए जाने का, नई रेल लाइनों के निर्माण, लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण, प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, आरओबी-आरयूबी के निर्माण, नई लंबी दूरी की लाइनों की शुरुआत और रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ किए जाने विशेष रूप से बिहार के कोसी-सीमांचल क्षेत्र के वारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

3. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के कोसी-सीमांचल क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्णिया जिले में कृषि और स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने और औद्योगिक क्लस्टर, साझा सुविधा केंद विपणन सहायता, कौशल विकास और निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

4. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कोशी नदी के व्यापक प्रबंधन और विकास परियोजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता, जिसमें वैज्ञानिक ड्रेजिंग, तटबंधों को मजबूत करना बहुउद्देशीय जलाशय, नियंत्रित जल प्रवाह प्रणाली, सिंचाई विस्तार, जलविद्युत उत्पादन और प्रभावित जनसंख्या के पुनर्वास के लिए एक विशेष पैकेज शामिल है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

5. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कोशी-सीमांचल क्षेत्र की रणनीतिक, व्यापारिक और कृषि परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सीमावर्ती सड़कों, लॉजिस्टिक कॉरीडोर्स, बाढ़ प्रभावित दोनों में हर मौसम वाली आंतरिक सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे सहित बहुआयामी कनेक्टिविटी के विकास के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान करने और समय सीमा निर्धारित किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

6. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में कोशी-सीमाचल क्षेत्र के पूर्णिया में नेपाल सीमा के साथ पर्यावरण पर्यटन सर्किट, कोशी नदी तट. पक्षी अभयारण्य और आर्द्रभूमि पर्यटन,

जनजातीय पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी विकसित किए जाने के लिए विशेष वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

7. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में नमामि गंगा कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने, गगा की सहायक नदियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने, नदी तल की वैज्ञानिक सफाई करने और गंगा नदी के किनारे रहने वाली आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष वितीय पैकेज प्रदान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

8. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में गया जी से पटना-मधेपुरा होते हुए काठमाडू (नेपाल) तक एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे औद्योगिक गलियारे के निर्माण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जान का, साथ ही बहु-आयामी लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक क्लस्टर और सीमा पार कार्गो टर्मिनल की स्थापना किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

9. कि पस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में पूर्णिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स, आईआईटी, आईआईएम और एनआईएफटी जैसी संस्थाओं की स्थापना के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

10. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-"किंतु खेद है कि अभिभाषण में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोशी-सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया के जिला-सह-मंडल मुख्यालयों की ग्राम पंचायतो में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए एकमुश्त निधि उपलब्ध कराए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

20. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में केंद्र सरकार के अधीन रिक्त पड़े विभिन्न पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

21. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की आय दोगुनी करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की विधिक गारंटी, खेती की बढ़ती लागत और ऋण राहत जैसे मुद्दों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

22. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विद्युतकरघा बुनकरों को सस्ती दरों पर बिजली देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

23. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उच्च न्यायिक सेवा आयोग बनाए जाने और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पदों में अनुसूचित जातिर्यो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

24. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के नागरिकों का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

25. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

26. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में सभी बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमो के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

27. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में अयोध्या से वाराणसी तक एक्सप्रेसवे बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

28. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती बेरोज़गारी, महंगाई और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए ठोस समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

29. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में युवाओं को रोज़गार, शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा दिए जाने के लिए किसी स्पष्ट नीति या रोडमैप के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to move:

30. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to take strong measures to tackle widespread coastal erosion that is swallowing up vast kilometres of our coastline particularly in Kerala and destroying hundreds of homes of our fishing communities and the need to provide relief or compensation to this community."

31. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to provide a stronger legal and financial backing for the establishment of a National Clean Air Mission or Swacchh Vayu Abhiyan in order to ensure

its successful implementation and offer a comprehensive solution to tackle India's deteriorating crisis of severe air pollution, that is resulting in the deaths of thousands of Indians annually."

32. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to address the issue of rampant drug abuse among the youth of the country and the need of measures to eradicate the production and distribution of banned narcotic substances."

33. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to institute either a dedicated Ministry of Fisheries to look after the socio economic welfare of our fishermen or the creation of a special Forum of Coastal MPs so that greater attention could be given to the plight faced by one of the most marginalised sections of our society."

34. That at the end of the motion, the following be added, namely:
"but regret that there is no mention in the Address about the need to enact legislation that will mandate the establishment of a bench of the High Court in the capital of each state including Kerala, for the convenience of petitioners and speedy judicial disposal of legal matters involving the state government."

35. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to take steps to establish the National University for Rehabilitation Sciences and Disability Studies by upgrading the erstwhile National Institute of Speech and Hearing in Thiruvananthapuram, as previously assured by the government."

36. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to take steps for establishment of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Kerala to boost the quality of medical services for residents of Kerala and Tamil Nadu."

37. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to take strong measures, including assistance, to tackle the problem of

unemployment in the country exacerbated by unfilled vacancies in government departments and the reported mass layoffs by private companies."

38. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to restore the fare concessions to senior citizen railway passengers."

39. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to incorporate legal protections for work-life balance, and limiting working hours for the workforce, the absence of which is negatively affecting the physical and mental well-being of the youth."

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

40. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about a special package for poverty alleviation and inclusive growth including welfare of marginalised community and women."

41. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about special project for employment creation of youth in MSME and further strengthening of Startup ecosystem."

42. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about the need for ensuring transparency and accountability in governance, electoral and administrative reforms."

43. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about a vision for federal cooperation, cultural diversity and unity, and strengthening the democratic institutions."

44. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about an effective scheme or programme for preventing cyber crime and improving police reforms and judicial efficiency."

45. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about effective project for ensuring smart city, urban planning, public transport and sanitation."

46. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about comprehensive scheme for strengthening the digital governance, e-services, cyber security and data protection."

47. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about an effective scheme for improving public health infrastructure and ensuring that all citizens are covered by Ayushman Bharat and ensuring health insurance to all."

48. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about an effective scheme for ensuring research, innovation, global competitiveness and digital education."

49. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about an effective programme for agricultural reform, and for irrigation, infrastructure and storage facilities for agricultural produce."

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I beg to move:

50. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about continued neglect of the Sundarban region in West Bengal and inadequate release of central funds for climate protection and livelihood support."

51. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the delay in release of central assistance under the Pradhan Mantri Awas Yojana, adversely affecting housing for the poor in West Bengal."

52. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the stoppage and shortage of Central funds under the Jal Jeevan Mission, hampering rural water supply projects in West Bengal."

53. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the nonrelease of central funds under MGNREGA, resulting in delayed wages and loss of livelihood for workers in West Bengal."

54. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the shortfall of central support under the National Rural Health Mission, weakening primary healthcare delivery in West Bengal."

55. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about growing inequality and concentration of wealth in the country."

56. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the continuing agrarian distress and rising farmer indebtedness."

57. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the large-scale vacancies in government services and the increasing contractualization of public employment."

58. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the alleged shrinking of financial autonomy of States thereby eroding the Federal Principles."

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): I beg to move:

59. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about the severe air pollution affecting major urban centres, including the national capital and lack of a credible national strategy to address climate-linked health risks."

60. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the continued delay and non-release of funds to States under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, particularly to Tamil Nadu, causing wage arrears and distress to rural workers."

61. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the adverse impact of recent tariff measures imposed by the United States on India's exports, particularly affecting export-oriented sectors such as textiles, leather, automobiles, electronics and MSMEs in Tamil Nadu."

62. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about inadequate and delayed financial assistance from the Union Government for Metro Rail projects in Tamil Nadu, including Chennai Metro Rail Phase II, and the non-consideration of proposals for Metro Rail projects in cities such as Madurai and Coimbatore."

63. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the contradiction between claims of high manufacturing growth and the huge unemployment faced by educated youth."

64. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the increasing centralisation of fiscal powers through reduced tax devolution, conditional grants and cesses, resulting in States bearing greater responsibilities without commensurating financial resources."

65. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the alleged dilution of labour protections through the new labour codes and the absence of meaningful consultation with trade unions and State governments."

66. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to consider the States' perspectives in the designing and implementation of centrally sponsored schemes promoting the spirit of cooperative federalism."

67. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about safeguarding linguistic diversity and ensuring equal respect to all classical and

regional languages, including Tamil, in governance, education and official communication."

SHRI ARUN NEHRU (PERAMBALUR): I beg to move:

78. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to allocate dedicated funds for the expeditious completion of the long-pending Perambalur-Namakkal and Ariyalur-Perambalur railway projects to enhance regional connectivity and economic integration."

79. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the establishment of a Mega Onion and Maize Processing Cluster in Perambalur district to promote value addition, reduce post-harvest losses, and augment income of local farmers."

80. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the sanction of a special central financial package for comprehensive irrigation and groundwater recharge projects in the drought-affected Veppanthattai and Thuraiyur blocks to sustain agrarian livelihoods."

81. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about specific measures to revitalise the Perambalur Special Economic Zone (SEZ) through targeted central incentives to spur local employment and manufacturing."

82. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the necessity to accelerate the time-bound four-laning of NH-136 and the construction of the Musiri-Kulithalai bypass to resolve critical traffic bottlenecks and facilitate seamless trade logistics."

83. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to revisit provisions of the National Education Policy (NEP) to safeguard the linguistic autonomy of States and respect the long-standing

twolanguage policy of Tamil Nadu, thereby upholding the principles of cooperative federalism."

84. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to address persistent concerns regarding the adverse impact of NEET exams on students from rural and economically marginalised backgrounds particulars in the state of Tamil Nadu."

PROF. VARSHA EKNATH GAIKWAD (MUMBAI NORTH-CENTRAL): I beg to move:

129. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about the agrarian crisis and increasing suicide by farmers in the country and steps to ensure remunerative income to farmers."

130. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the increasing unemployment in the country or need for providing unemployment allowance."

131. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to develop a mechanism to control the prices of petrol, diesel and other petroleum products."

132. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the alleged increase in atrocities against Scheduled Castes, Scheduled Tribes, women and children."

133. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to address the causes for depreciation of Indian rupee."

134. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the violation of rights of slum dwellers in the name of redevelopment."

135. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the growing economic inequality in the country."

136. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the alleged dilution of independence of constitutional bodies."

137. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the closure of large number of micro, small and medium enterprises leading to rise in job losses."

138. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the impact of imposition of high tariffs by the United States of America on our country."

DR. KADIYAM KAVYA (WARANGAL): I beg to move:

160. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV) for mobilising funds and exemption of loans raised through the SPV from the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) limits in the State of Telangana."

161. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the proposal to include institutions not mentioned anywhere in Schedule X of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 for their apportionment between the two Telugu States — Telangana and Andhra Pradesh."

162. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about allegedly withholding of funds meant for opposition-ruled States."

163. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about allegedly misusing of central agencies in poll-bound States."

164. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about rolling back of the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Act, 2025."

165. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about ruling out the apprehensions among people regarding the Special Intensive Revision (SIR) exercise."

166. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about any effective steps undertaken to check terrorist attacks in the country."

KUMARI SUDHA R. (MAYILADUTHURAI): I beg to move:

167. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about establishment of a new airport in Mayiladuthurai or Kumbakonam to support the anticipated influx of pilgrims and promote spiritual tourism in the region."

168. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the high risk of rise in sea-levels and the necessity to build protective structures such as sea walls and groynes to safeguard against coastal flooding in vulnerable areas like Sirkazhi, Poompuhar, Pazhayar and Tharangambadi and need to allocate resources for immediate coastal resilience initiatives to protect lives, livelihoods and heritage sites."

169. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the severe agricultural losses caused by cyclone Ditwah and the critical need for loan waivers for affected farmers, and need to implement comprehensive relief measures including debt relief schemes and rehabilitation for restoring agricultural productivity."

170. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the widespread damage to fishing equipment, including boats, nets, GPS devices and engines due to cyclones, other natural calamities crippling the livelihoods of coastal communities and the need to provide compensation and replacement schemes."

171. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the Indian fishermen being detained and arrested by foreign countries, including Sri Lanka violating human rights and disrupting maritime livelihoods, and the need to strengthen bilateral negotiations and ensure swift repatriation and legal support for affected fishermen and their families."

172. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the potential for development or revival of ancient ports like Poompuhar to enhance maritime trade, tourism, undertake cultural preservation and the need to invest in restoration projects that integrate historical significance with modern economic opportunities for coastal regions."

173. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the persistent gender gap in India's higher judiciary undermining diversity and equitable representation in the justice system, and to implement affirmative measures and reforms to promote gender parity in judicial institutions."

174. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need for establishing Kendriya Vidyalayas in Mayiladuthurai or Kumbakonam."

175. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the establishment of an exclusive cluster or individual units for producing fishing nets and equipments for empowering local industries, reducing import dependency and supporting sustainable fisheries and initiatives for skill training, subsidies and technological upgradation for coastal communities."

176. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the importance of underwater archaeological explorations at Poompuhar to uncover ancient maritime history and promote heritage tourism, funding specialized expeditions, collaborating with experts and integrating findings into national cultural preservation efforts."

SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR): I beg to move:

177. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the deepening employment crisis particularly among youth, nor does it outline a coherent strategy for large-scale job creation and skill development aligned with the evolving needs of the economy."

178. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about targeted measures to be undertaken to strengthen educational access, skill acquisition and meaningful industry participation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to overcome the persistent disparities in learning outcomes, employability and representation in formal economic sectors."

179. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the stagnation and uneven outcomes in several Aspirational Districts, and the need for a renewed roadmap to address gaps in employment opportunities, education, healthcare and local economic development for focused and transformative intervention."

180. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the widespread protests by workers and trade unions against the labour codes, the uncertainty created by the repeal of MGNREGA and the continuing distress faced by poor and informal workers, including falling real wages, weak social security."

SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR): I beg to move:

187. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the implications of the decision of the US Administration to dissociate itself from 66 international organizations out of which 31 linked to United Nations (UN), involved in activities such as United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and also others like the International Solar Alliance, UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) etc. which may have disastrous effect on the activities of related sectors."

188. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the declining share of central funding in the centrally sponsored schemes (CSS) that could disproportionally affect poorer states adversely and will have serious impact on the implementation of such schemes."

189. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about India becoming world's fourth largest economy and the aggregate GDP comparisons though the per capita income which remains very low due to population size of our country."

190. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about India's nonreaction to the unilateral US tariff hike war and other major international developments such as the situation in Venezuela or statement threatening the annexation of Greenland."

191. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to provide Provident Fund (PF), Employees State Insurance (ESI) and other social security benefits to the "Scheme based workers" as per the recommendations of the 45th Indian Labour Conference."

192. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about gross underutilization of the funds under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana (PMGSY) in last two years and meagre utilisation during the current financial year."

193. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the state of India's Research and Development expenditure which is merely 0.6-0.7% of GDP placing the country at 38th position in the Global Innovation Index 2025."

194. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to reduce air pollution especially PM2.5 levels in the country to the globally acceptable levels."

195. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the promise made by the Government during the 2014 elections that the employment generation will be top priority."

196. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the Comptroller and Auditor General of India (CAG) report which has identified some glaring irregularities in the implementation of the centre's flagship skills training initiative under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) in three phases from 2015 to 2022."

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): I beg to move:

216. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the spirit of cooperative federalism and increasing centralisation of fiscal, administrative and legislative powers. "
217. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the declining share of States in divisible tax revenue and the adverse impact of reduced fiscal transfers on development-oriented States."
218. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the alleged structural deficiencies in the GST regime, including delayed compensation and loss of fiscal autonomy for States."
219. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the inequitable allocation of central funds due to which the fiscally disciplined and high-performing States have been suffering adversely."
220. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the adverse impact of the alleged excessive centralisation in education policy, undermining State innovation and local needs."
221. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the alleged delays in wage payments under the rural employment schemes especially under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) and the 60:40 sharing of expenditure under the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025."
222. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the alleged social inequities caused by uniform entrance examinations such as NEET."

SHRI RAJEEV RAI (GHOSI): I beg to move:

240. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the urgent need to restore the Old Pension Scheme (OPS) for government employees in view of the fact that only around 3% of eligible employees are allegedly opting for Unified Pension Scheme (UPS)."

241. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the problems arising from the implementation of the UGC (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023 and the need to ensure regulatory parity and institutional equity between foreign and Indian higher-education institutions."

242. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the measures to ensure a dignified life for senior citizens, including the need for a National Commission for Senior Citizens to safeguard their rights, provide independent grievance redressal and improve policy coordination."

243. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the adverse impact and hardship caused to Indian exporters and small-scale industries due to unilateral hike in tariff on Indian exports by the United States of America."

244. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the high unemployment rate existing in the country and any roadmap to address the cause."

245. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the growing threat posed by deepfakes and artificial intelligence and the need for safeguards such as granting copyright over human faces, as adopted in countries like Denmark, to prevent misuse and protect individual dignity and privacy."

246. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the miserable conditions of the weaving industries particularly in Mau district and adjoining

region of Eastern part of Uttar Pradesh and a need to improve the sector with adequate financial and relief packages, and alleviate the sufferings of weavers engaged in this sector and stopping the migration of large number of youth from the region."

247. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need for providing loan facility at subsidised rate of interest to farmers through primary cooperative banks, rural banks and commercial banks."

248. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the need to provide financial and marketing assistance to protect small and traditional industries and persons in retail trade in the wake of entry of big multinational companies and big industrial houses."

249. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the difficulties being faced by farmers due to lack of life insurance measures for farmers dying in harness and very limited coverage of the number of crops under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana."

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): I beg to move:

250. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
“but regret that there is no mention in the Address about the tragic Ahmedabad air crash, the loss of precious lives therein and the absence of accountability, transparent investigation, and systemic reforms to ensure aviation safety."

251. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the inordinate delay in the Chandigarh Metro Rail Project, leading to cost escalation, traffic congestion, environmental degradation, and hardship to residents of the Tricity region."

252. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the recent bomb blast in Delhi, identifying the lapses in intelligence and urban security preparedness, and the measures taken to prevent such incidents in the future."

253. That at the end of the motion, the following be added, namely:-

"but regret that there is no mention in the Address about the worsening pollution crisis across major cities, including severe air and water pollution, and the failure of existing action plans to protect public health."

254. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the continuous fall of the Indian rupee, its impact on inflation, imports, household savings, and the absence of a clear strategy to stabilise the currency."

255. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the adverse impact of increased tariffs imposed by the United States on Indian exports, and the lack of a robust diplomatic and trade response to safeguard Indian industry and employment."

256. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about aviation sector, including the failure of the UDAN scheme, closure or grounding of several regional airports, and the absence of connectivity in aspirational and remote regions."

257. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the untimely and devastating floods during the recent monsoon that severely affected Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, causing loss of lives, crops, infrastructure and livelihoods."

258. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about India's increasing vulnerability to climate change, including extreme weather events, and the lack of a comprehensive national preparedness and adaptation strategy."

259. That at the end of the motion, the following be added, namely:-
"but regret that there is no mention in the Address about the lack of regular desilitation of dams and reservoirs across the country, resulting in reduced storage capacity, increased flood risks and water insecurity."

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

260. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य में न्यायिक अवसंरचना के विस्तार, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालय की दूसरी पीठ की स्थापना की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

261. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में रेलवे के आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण के दावों के बावजूद वर्षों से लंबित होने वाली गया डाल्टनगंज रेलवे लाइन-शेरघाटी सहित बिहार की अनेक स्वीकृत रेलवे परियोजनाओंऔर साथ हीइनके शीघ्र क्रियान्वयन हेतु किसी समयबद्ध कार्ययोजना अथवा स्पष्ट बजटीय प्रतिबद्धता के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है।"

262. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विशेष औद्योगिक पैकेज, समान सुविधा केन्द्र, सस्ते ऋण एवं निवेश प्रोत्साहनों के संबंध में किसी स्पष्ट रोडमैप के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

263. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य की दो अत्यंत महत्वपूर्ण जीवनरेखा सड़कों--डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-गया-पटना 119 (एनएच-2) के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी, जो औद्योगिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न कर रही है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

264. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के औरंगाबाद जिले में व्याप्त नल है पर पानी' की स्थिति 'नहींऔर अनेक पंचायतों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने से सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच स्पष्ट अंतर के दिखने तथा साथ ही, कोसी मेची नदी-इंटरलिकिंग परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की तात्कालिक आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

265. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
किंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत को वैश्विक बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बावजूद बिहार के बौद्ध सर्किट, गया के विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना तथा औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर एवं उमगा मंदिर के संदर्भ में सड़क एवं रेल संपर्क, आवास, स्वच्छता, अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी और स्थानीय रोजगार सृजन हेतु किसी समय एवं समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

266. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
किंतु खेद है कि अभिभाषण में जैसी योजनाओं 'लखपति दीदी के बावजूद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के अनुसार बिहार में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी कम होने तथासाथ हीछात्रावासों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी राष्ट्रीय न्यूनतम मानक या जवाबदेही तंत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

267. कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थातः-
"किंतु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

—-

HON. CHAIRPERSON: Shri G.M. Harish Balyogi.

… (*Interruptions*)

1413 hours

SHRI G.M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Hon. Chairperson, I rise today on behalf of my Telugu Desam Party to extend our support to the gracious Address delivered by the hon. President. The Address presents a confident national roadmap, anchored in reform, guided by inclusion and directed towards the long-term objective of building a strong, self-reliant and globally competitive India.

The vision of Viksit Bharat 2047 reflects a fundamental shift in governance, philosophy from managing short-term outcomes to shaping India's long-term economic and institutional capacity and strategic relevance in global economy. With India's potential growth rate approaching seven per cent, driven by sustained reforms and historical public investment, we are witnessing the emergence of a new development trajectory. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1414 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पंद्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1500/GG/GTJ)

1501 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Everybody, please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Rahul ji, please be seated.

… (*Interruptions*)

सदस्यों का नाम लेना तथा निलंबन

1501 बजे

माननीय सभापति : श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री हैबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी, श्री सु. वेंकटेशन और श्री बी. मणिक्कम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभा पटल पर नारेबाजी कर रहे थे और पेपर्स फाड़कर फेंक रहे थे, इसीलिए मैं इन सबका नाम ले रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री किरेन रिजिजू जी।

… (व्यवधान)

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS

1502 hours

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:

> "That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri B. Manickam Tagore, Shri Amrinder Singh Raja Warring, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Hibi Eden, Dr. Prashant Yadaorao Padole, Adv. Dean Kuriakose, Shri S. Venkatesan and Shri Chamala Kiran Kumar Reddy in utter disregard to the House and the authority of the Chair through reaching to the Table of the Secretary-General and other officers in the well of the House and throwing papers on the Chair, and having been named by the Chair, resolves that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374 (2)." … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के निलंबन हेतु जो प्रस्ताव पेश किया है, अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

*The question is :

> "That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri B. Manickam Tagore, Shri Amrinder Singh Raja Warring, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Hibi Eden, Dr. Prashant Yadaorao Padole, Adv. Dean Kuriakose, Shri S. Venkatesan and Shri Chamala Kiran Kumar Reddy in utter disregard to the House and the authority of the Chair through reaching to the Table of the Secretary-General and other officers in the well of the House and throwing papers on the Chair, and having been named by the Chair, resolves that the above-mentioned Members may be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374 (2)." … (*Interruptions*)

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

---

* Original in Hindi

HON. CHAIRPERSON: Everybody, please be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1504 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 4 फरवरी 2026 / 15 माघ, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।